

“एक राष्ट्र, एक चुनाव” 129वाँ संवधान संशोधन विधियक 2024

प्रलिस के लयि:

129वाँ संवधान संशोधन विधियक, 2024 की मुख्य वशिषताएँ, [संवधान संशोधन विधियक](#), [लोकसभा](#), [राष्ट्रपति](#), [जम्मू-कश्मीर पुनरगतन अधनियम, 2019](#)

मेन्स के लयि:

विधियक की मुख्य वशिषताएँ, भारत में एक राष्ट्र, एक चुनाव के नहितारथ

[स्रोत: पी.आई.बी](#)

चर्चा में क्यो?

हाल ही में, सरकार ने [लोकसभा](#) में दो [संवधान संशोधन विधियको](#) “एक राष्ट्र, एक चुनाव”-‘129वाँ संवधान संशोधन विधियक, 2024’ और ‘केंद्रशासति प्रदेश कानून संशोधन विधियक, 2024’ को पेश करके “एक राष्ट्र, एक चुनाव” को लागू करने की दशा में बड़ा कदम उठाया है।

- भारत में वर्ष 1951 से 1967 तक लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजति कयि गए थे।

विधियक की मुख्य वशिषताएँ क्या हैं?

- ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ 129वाँ संवधान संशोधन विधियक 2024: विधियक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को संरेखति करने के लयि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोवदि की अध्यक्षता वाली समिति की सफारिश पर संवधान में **अनुच्छेद 82A (1-6)** को जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है।
 - अनुच्छेद 82 (1-6):**
 - 82A (1)** में राष्ट्रपति द्वारा आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तथि में प्रस्तावति परिवर्तनों को लागू करने के लयि समय-सीमा का प्रावधान कयि गया है, जसि “नयित तथि (Appointed Date)” के रूप में नरिदषिट कयि गया है।
 - धारा 82(2)** में कहा गया है कि नयित तथि के बाद और लोक सभा का पूर्ण कार्यकाल समाप्त होने से पहले नरिवाचति सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल लोक सभा के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगा।
 - अनुच्छेद 82A (3)** में कहा गया है कि भारत का नरिवाचन आयोग (ECI) लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लयि एक साथ आम चुनाव कराएगा।
 - अनुच्छेद 82A (4)** एक साथ चुनावों को “लोकसभा और सभी विधानसभाओं के एक साथ गठन के लयि आयोजति आम चुनाव ” के रूप में परभाषति करता है।
 - अनुच्छेद 82A (5)** भारत का नरिवाचन आयोग को लोकसभा चुनाव के साथ कसि वशिष विधानसभा चुनाव न कराने का वकिलप प्रदान करता है।
 - भारत का नरिवाचन आयोग राष्ट्रपति को कसि विधान सभा के लयि बाद में चुनाव कराने की अनुमति देने हेतु आदेश जारी करने की सलाह दे सकता है।
 - अनुच्छेद 82A (6)** में कहा गया है कि यदि कसि विधानसभा का चुनाव स्थगति कर दयि जाता है तो उस विधानसभा का पूर्ण कार्यकाल भी आम चुनाव में नरिवाचति लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगा।
 - अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन:**
 - विधियक के अनुसार, यदि लोकसभा अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग हो जाती है, तो अगली लोकसभा केवल शेष अवधितक ही कार्य करेगी, जसि “वधितन की तथि और पहली बैठक की तथि से पाँच वर्ष के बीच की अवधि” के रूप में परभाषति कयि गया है।
 - इसका अर्थ यह है कि सदन के पूर्ण कार्यकाल तक चलने के बाद भी, जो विधियक अभी भी लंबति है, उनकी समय-सीमा समाप्त हो जाएगी।
 - राज्य विधानसभाओं के लयि अनुच्छेद 172 में संशोधन प्रस्तावति कयि गया है, जो राज्य विधानसभाओं की अवधि को नरिंतरति करता है।
 - यदि कसि राज्य विधानसभा को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले भंग कर दयि जाता है, तो पछिली विधानसभा के शेष

कार्यकाल के लिये चुनाव कराए जाएंगे।

- अनुच्छेद 372 में संशोधन:
 - वधियक में अनुच्छेद 372 में संशोधन का प्रस्तावति है, जिसमें "नरिवाचन कषेत्रों के परसीमन" के बाद एक साथ चुनाव कराने को शामिल कया जाएगा, जिससे राज्य वधियन सभा चुनावों पर संसद की शक्तिका वसितार होगा।
 - इस वधियक में स्थानीय नकियों और नगर पालकियों के चुनाव को शामिल नहीं कया गया।
- केंद्रशासति प्रदेश कानून संशोधन वधियक 2024:
 - वधियक का उद्देश्य संघ राज्य कषेत्र शासन अधनियम, 1962 की धारा 5, राष्ट्रीय राजधानी कषेत्र दलिली शासन अधनियम, 1991 की धारा 5 तथा जममू-कश्मीर पुनरगठन अधनियम, 2019 की धारा 17 में संशोधन करना है, ताकलोकसभा और राज्य वधियनसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सकें।

भारत में चुनाव से संबंधति संवैधानकि प्रावधान क्या हैं?

- भाग XV (अनुच्छेद 324-329): यह चुनाव और उनसे संबंधति मामलों के लिये आयोग की स्थापना के प्रावधान से संबंधति है।
- अनुच्छेद 324: यह नरिवाचन आयोग को संसद और राज्य वधियनसभाओं के चुनावों की संपूर्ण प्रक्रया का पर्यवेक्षण, नरिदेशन तथा नरियंत्रण करने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 325: इसमें लोकसभा और राज्य वधियनसभाओं के सभी चुनावों के लिये एकल नरिवाचक नामावली की स्थापना का प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद 326: यह नरिदषिट करता है कलोकसभा और राज्य वधियनसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारति होंगे।
- अनुच्छेद 82 और 170: ये नषिपक्ष प्रतनिधित्व सुनश्चिति करने के लिये प्रत्येक जनगणना के बाद नरिवाचन कषेत्रों का परसीमन अनवर्य कयि जाने से संबंधति हैं।
- अनुच्छेद 172: इसके अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक वधियनसभा, यदापहले ही वधितति नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधविशन के लिये नरियत तारीख से पाँच वर्ष तक बनी रहेगी।

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर उच्च स्तरीय समति की रपिर्त

- समति का गठन और उद्देश्य:
 - पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोवदि की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समति का गठन केंद्र सरकार द्वारा सतिंबर 2023 में कया गया था।
 - समति को लोकसभा, राज्य वधियनसभाओं और स्थानीय नकियों के लिये एक साथ चुनाव कराए जाने की व्यवहार्यता की जाँच करने का कार्य सौंपा गया था।
- एक साथ चुनाव कराए जाने का औचित्य:
 - समति ने स्पष्ट कया कबार-बार चुनाव कराए जाने से अनश्चितता की स्थति उत्पन्न होती है, जबकि एक साथ चुनाव कराए जाने से स्थरि शासन सुनश्चिति होगा और व्यवधान कम होंगे।
 - इसके अतरिकित, एक साथ चुनाव कराए जाने से लागत में कमी आने और मतदाता की सहभागति बढ़ने की उम्मीद है।
- नरिवाचक नामावली प्रबंधन:
 - नरिवाचन प्रक्रया को सुव्यवस्थति करने के लिये समति ने राज्य नरिवाचन आयोगों (SEC) के परामर्श से भारत के नरिवाचन आयोग (ECI) द्वारा तैयार एकल नरिवाचक नामावली के अंगीकरण का सुझाव दया।
 - इससे दोहराव कम होगा और नरिवाचन के प्रबंधन में शामिल वभिन्न एजेंसियों की कार्यकुशलता में सुधार होगा।
- रसद व्यवस्था:
 - समति ने इस बात पर ज़ोर दया कECI और SEC दोनों को एक साथ होने वाले चुनावों के दौरान सुचारु क्रयान्वयन सुनश्चिति करने के उद्देश्य से रसद व्यवस्था करने हेतु वसितृत आयोजना और उसका आकलन करना चाहयि।

एक साथ चुनाव कराए जाने से संबंधति चुनौतियाँ क्या हैं?

- बुनयादी ढाँचे का वकिस: एक साथ चुनाव कराए जाने की जटलिताओं से नपिटने के लिये तकनीकी बुनयादी ढाँचे की पर्याप्त उपलब्धता सुनश्चिति करना महत्त्वपूर्ण है।
 - इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटगि मशीन (EVM) और वोटर वेरफिएबल पेपर ऑडिट टरेलस (VVPAT) का प्रभावी परनियोजन और प्रबंधन शामिल है।
 - 2024 के आम चुनावों में, समग्र देश के 1.05 मलियन मतदान केंद्रों पर लगभग 1.7 मलियन नरियंत्रण एकक और 1.8 मलियन VVPAT प्रणालियों का परनियोजन कया गया था।
- वधिकि चुनौतियाँ: कसी भी संशोधन और एक साथ चुनाव क्रयान्वति करने की प्रक्रया को वधिकि चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और संवैधानकि प्रावधानों के अनुपालन को सुनश्चिति करने के लिये नयायकि जाँच की आवश्यकता हो सकती है।
- कषेत्रीय असमानताएँ: कुछ राजनीतिक दलों का मत है कएक साथ चुनाव कराए जाने से राष्ट्रीय अभयान के दौरान कषेत्रीय हतियों और मुद्दों की उपेक्षा हो सकती है।
 - वविधि प्रतनिधित्व बनाए रखने हेतु यह सुनश्चिति करना महत्त्वपूर्ण है कस्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय हतियों से प्रभावति न हों।
- प्रशासनकि चुनौतियाँ: वभिन्न राज्यों में एक साथ चुनाव आयोजति करने से अनेक चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं, जनिमें मतदाता सूचियों का प्रबंधन

और सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है।

- नागरिकों को नई नरिवाचन प्रक्रिया और उसके नहितार्थों के बारे में जानकारी देने के लिये एक व्यापक मतदाता शिक्षा अभियान की आवश्यकता होगी।

एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिये कौन-सी रणनीति अपनाई जा सकती है?

- **वधिक स्पष्टता:** एक साथ चुनाव कराने के लिये स्पष्ट नरिदेश स्थापित करना, मतदाता पंजीकरण के लिये कार्यक्रम और प्रक्रियाओं का वविरण देना।
 - सरकार के सभी स्तरों पर चुनावों के समन्वयन को सुगम बनाने के लिये आवश्यक संवैधानिक संशोधन को सुनिश्चित किये जाने चाहिये।
- **चुनावी बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करना:** कोवदि समिति की सफ़िरशि के अनुसार, एक ऐसी एकीकृत मतदाता सूची प्रणाली वकिसति की जानी चाहिये, जो सरकार के तीनों स्तरों लोकसभा, राज्य वधानसभाओं और स्थानीय नकियायों के लिये उपयोगी हो, तार्का दोहराव और त्रुटियों को कम कयिा जा सके।
 - मतदाता सत्यापन और परणामों के सारणीकरण समेत चुनावी प्रक्रियाओं के कुशल प्रबंधन के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।
 - चुनाव आयोग की सफ़िरशों (2016) में मतदाता पंजीकरण और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिये प्रौद्योगिकी के उपयोग सहति चुनावी प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिये परविरतनों का सुझाव दयिा गया था।
- **जन जागरूकता अभियान:** मतदाताओं को एक साथ चुनाव कराने के लार्भों और उनके मतदान अनुभव पर इसके प्रभाव के बारे में सूचति करने के लिये देशव्यापी अभियान शुरू करना।
 - प्रस्तावति परविरतनों पर सूचना प्रसारति करने और जनता से फीडबैक एकत्र करने के लिये सरकारी संगठनों तथा सामुदायिक संगठनों को शामिल करना।
- **क्षमता नरिमाण:** सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये एक साथ चुनावों से जुड़ी नवीन प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं पर चुनाव अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण सत्र आयोजति करना।

दृष्टि भेन्स प्रश्न

प्रश्न: भारत में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को लागू करने के नहितार्थों का आलोचनात्मक वश्लेषण कीजयि। क्षेत्तीय प्रतनिधित्व और प्रशासनिक दक्षता से संबंधति चुनौतियों का भी उल्लेख कीजयि।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

????????

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2017)

1. भारत का नरिवाचन आयोग पाँच सदस्यीय नकियाय है।
2. संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनावों दोनों के लिये चुनाव कार्यक्रम तय करता है।
3. नरिवाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के वभिजन/वलय से संबंधति वविाद नपिटाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (d)

??????

प्रश्न. आदर्श आचार-संहति के उद्भव के आलोक में, भारत के नरिवाचन आयोग की भूमिका का वविचन कीजयि। (मुख्य परीक्षा, 2022)

